



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 8, 2018/माघ 19, 1939

No. 58]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 8, 2018/MAGHA 19, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2018

(मामला सं. एसएसआर 01/2018)

(जांच शुरूआत)

(निर्णायक समीक्षा)

**विषय : चीन जन. गण. से फ्लैट बेस स्टील व्हिल्स के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत ।**

**फा. सं. 7/1/2018-डीजीएडी 1.**—1995 और उसके बाद यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 16" आकार से 20" के नगण्य व्यास के फ्लैट बेस स्टील व्हिल्स, नगण्य व्यास का प्रयोग वाणिज्यिक वाहनों में ट्यूब टायर अनुप्रयोगों में किया जाता है (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।

2. यतः संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जाँच प्राधिकारी द्वारा 21 मई, 2006 की अधिसूचना सं. 14/8/2005-डीजीएडी के माध्यम से शुरू की गई थी। प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जाँच परिणाम 12 जनवरी, 2007 की अधिसूचना सं 14/8/2005-डीजीएडी द्वारा जारी किए गए थे और राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना सं 51/2007-सीमाशुल्क दिनांक 29 मार्च, 2007 के जरिए अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जाँच परिणाम 28 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना सं 14/8/2005-डीजीएडी द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। अंतिम जाँच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिसूचना सं 124/2007-सीमाशुल्क दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 के जरिए 29 मार्च, 2007 से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

3. यतः, कुछ हितबद्ध पक्षों ने प्राधिकारी के अंतिम जाँच परिणाम के विरुद्ध सेस्टेट के समक्ष अपीलें दायर की थीं। माननीय सेस्टेट ने दिनांक 11 अगस्त, 2011 के अपने आदेश द्वारा मामले को निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपीलकर्ताओं की निर्णय के बाद सुनवाई करने के लिए वापस भेजा और निर्णय के बाद के इस सुनवाई के परिणामस्वरूप अंतिम जाँच परिणाम में जितने आशोधन आवश्यक हों, को करने के लिए कहा। यतः, माननीय सेस्टेट के आदेशों के अनुपालन में और विधि और सिद्धांत के मामलों से संबंधित आदेशों को चुनौती देने के निर्दिष्ट प्राधिकारी के अधिकारों पर विचार किए बिना प्राधिकारी ने 13 दिसम्बर, 2011 को ज्ञात हितबद्ध पक्षों के लिए निर्णय के बाद की मौखिक सुनवाई आयोजित की और 10 फरवरी, 2012 की अधिसूचना सं. 14/8/2005-डीजीएडी द्वारा निर्णय के बाद जाँच परिणाम जारी किए, जिसमें 28 नवम्बर, 2007 की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं 14/8/2005-डीजीएडी द्वारा किए गए अंतिम जाँच परिणाम और उसमें की गई सिफारिशों की पुनः पुष्टि की।

4. यतः प्राधिकारी द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2012 की अधिसूचना सं 15/22/2011-डीजीएडी द्वारा एक निर्णायक समीक्षा जाँच शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 20 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं. 15/22/2011-डीजीएडी द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की और वित्त मंत्रालय ने 26 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं 3/2013-सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ा दी।

5. यतः मै. कल्याणी मैक्सिकोन व्हिल्स प्रा. लि. और मै व्हिल्स इंडिया लिमिटेड ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों की ओर से प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने का आरोप लगाया गया है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया है।

#### **क. विचाराधीन उत्पाद**

#### **6. पूर्ववर्ती जाँच और वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार है :**

*चीन जन. गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फ्लैट बेस स्टील व्हिल्स जिनका आकार 16" के नामिनल व्यास से 20" के नामिनल व्यास का है जिसका प्रयोग वाणिज्यिक वाहनों के ट्यूब टायर अनुप्रयोगों में किया जाता है (संबद्ध वस्तु)।*

*फ्लैट बेस स्टील व्हिल्स एक डिमांडेबल रिंग के साथ रिम और डिस्क का संयोजन होता है। रिम्स और डिस्कों का उत्पादन पृथक लाइनों में होता है और इन्हें साथ में व्हिल के रूप में वेल्ड किया जाता है जिसे वाहनों के एक्सल पर लगाया जाता है और वाहनों को चलाने के लिए टायरों पर फिट किया जाता है। वाणिज्यिक वाहनों में बस, ट्रक,*

ट्रेलर, ट्रैम्पो आदि सहित लारियां शामिल हैं। व्हिल्स को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 86 में रेलवे और ट्रामवे रोलिंग स्टॉक इस इतर वाहनों और उसके कलपुर्जे और सहायक सामान"में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम और आईटीसी एचएस वर्गीकरण की श्रेणी के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

7. वर्तमान जाँच मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है और चूंकि पिछली जाँच से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई खास विकास नहीं हुआ है इसलिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे को मूल जाँच के समान ही रखना अपेक्षित है।

## ख. समान वस्तु

8. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) :- हैवस्थानुसार व्यमें निम्ना (

*“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;*

9. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। इन दोनों उत्पादों में भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताएं हैं।

## ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. यह याचिका मै. कल्याणी मैक्सिओन व्हिल्स प्रा. लि. और मै. व्हिल्स इंडिया लि. जो भारत में संबद्ध वस्तु के प्रमुख उत्पादक हैं, द्वारा दायर की गई है। स्टील स्ट्रिप्स व्हिल्स लि. द्वारा इस याचिका का समर्थन भी किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने प्रमाणित किया है कि वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादक/निर्यातक से न तो संबंधित हैं और न ही जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के का उन्होंने आयात किया है। अतः वह नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग माने जाने के पात्र हैं। प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ता कंपनियों को घरेलू उद्योग माना है और यह आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

## घ. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

11. प्रस्तुत किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा जाँच की शुरुआत करते हैं ताकि समीक्षा की जा सके कि क्या संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जाँच की जा सके कि क्या लागू शुल्क को हटाये जाने से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

## ङ. शामिल देश

12. इस जाँच में शामिल देश चीन जन. गण. है।

**च. जाँच अवधि (पीओआई)**

13. प्राधिकारी ने अक्टूबर, 2016 से सितम्बर 2017 की अवधि पर जाँच अवधि के रूप में विचार किया है। तथापि क्षति जाँच अवधि पर 2014-15, 2015-16, 2016-17 और जाँच अवधि के रूप में विचार किया गया है।

**छ. प्रक्रिया**

14. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में दिनांक 20 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं. 15/22/2011-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित अंतिम जाँच परिणाम, जिसमें चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लैट बेस स्टील व्हिल्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी, के सभी पहलू शामिल होंगे।

15. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

**ज. सूचना प्रस्तुत करना**

16. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकें और अपने विचारों से अवगत करा सकें:

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**  
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,**  
**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,**  
**5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

[dgad.india@gov.in](mailto:dgad.india@gov.in)

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

**झ. समय-सीमा**

18. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (दिनों 40) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में “उपलब्ध तथ्यों” के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरुआत की तारीख से चालीस दिनों (दिनों 40) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने

उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर और पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की आवश्यकता या अन्यथा के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

### ब. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

21. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

22. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### द. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

26. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

### ठ. असहयोग

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****Department of Commerce**

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th February, 2018

**(Case No. SSR 01/2018)****(Initiation)****(Sunset Review)****Subject: Initiation of Sunset review investigation concerning imports ‘Flat Base Steel Wheels’ from China PR**

**F.No. 7/1/2018–DGAD. 1.** Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of anti-dumping duty on imports of “Flat Base Steel Wheels of size 16” nominal diameter to 20” nominal diameter used in tubed tyre application in commercial vehicles” (hereinafter referred as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country).

2. WHEREAS, the original investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority *vide* Notification No. 14/8/2005-DGAD dated 21 May, 2006. The Preliminary Finding was issued by the Authority *vide* Notification No. 14/8/2005-DGAD dated 12 January, 2007 and the provisional anti-dumping duty was imposed by the Department of Revenue *vide* Notification No. 51/2007 Customs dated 29 March, 2007. The Final Findings Notification was issued by the Authority *vide* notification No.14/8/2005-DGAD dated 28 November, 2007; recommending imposition of definitive duty. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive antidumping duty was imposed w.e.f 29 March, 2007 by the Department of Revenue *vide* Notifications No. 124/2007-Customs dated 31st December, 2007 on the imports of the of the subject goods, originating in or exported from the subject country.
3. Whereas, some of the interested parties had filed appeals before CESTAT against the Final Findings of the Authority. The Hon’ble CESTAT *vide* its order dated 11 August, 2011 remanded the matter back to the Designated Authority for affording post-decisional hearing to the appellants and for making such modifications to the Final Findings as may be necessary as a result of such post decisional hearing. Whereas, in compliance with the orders of the Hon’ble CESTAT and without prejudice to the rights of the Designated Authority to challenge the orders on the matters of law and principle, the Authority held a post decisional oral hearing for the known interested parties on 13 December 2011 and issued the post decisional findings *vide* Notification No.14/8/2005-DGAD dated 10th February, 2012, re-affirming its final findings made *vide* earlier Notification No.14/8/2005-DGAD dated 28 November 2007 and the recommendations made therein.
4. Whereas, a sunset review investigation was initiated *vide* notification no 15/22/2011-DGAD dated 24th February, 2012 by the Authority. The Authority recommended continued imposition of definitive anti-dumping duties on the subject imports from the subject country *vide* notification No.15/22/2011-DGAD, dated 20<sup>th</sup> February, 2013 and Ministry of Finance extended definitive anti-dumping duty *vide* notification No.3/2013- CUS, dated the March 26, 2013 on all imports of the subject goods from the subject country.
5. Whereas, M/s. Kalyani Maxion Wheels Private Limited and M/s. Wheels India Limited have filed a duly substantiated application before the Authority, on behalf of the producers of the subject goods in India, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

**A. Product under consideration**

6. The product under consideration in the previous investigations as well as the present investigation is as under:

*“Flat base Steel Wheels of size 16” nominal diameter to 20” nominal diameter used in tubed tyre application in commercial vehicles” (the subject goods), originating in or exported from China PR.*

*Flat base steel wheels are assembly of rim and disc with a demountable ring. Rims and discs are produced in separate lines and welded together to form a wheel, which is mounted on the axles of vehicles and fitted with tyres to enable vehicle movement. Commercial vehicles comprise of buses, lorries including trucks, trailers, tempos, etc.*

*Wheels are classified under Chapter 87 of the Customs Tariff Act under the category of “vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof” under the sub-heading 8708.70 of the Customs Tariff Act and ITC HS classification. The customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.*

7. The present investigation is for sunset review of existing anti dumping duty and as there are no major developments since the previous investigations with regard to product under consideration, the scope of the product under consideration is required to be kept the same as that of original investigation.

**B. Like Article**

8. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

*"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;*

9. Petitioners have claimed that there is no known difference in subject goods exported from subject country and that produced by the domestic industry. Both the products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc.

**C. Domestic Industry and Standing**

10. The petition has been filed by M/s. Kalyani Maxion Wheels Private Limited and M/s. Wheels India Limited, who are the major producers of the subject goods in India. The petition has also been supported by Steel Strips Wheels Ltd. The petitioners have certified that they are neither related to producer/exporter of the product under consideration in subject country or nor have they imported the subject good from the subject country during the Period of investigation. Therefore, they are eligible to be treated as “domestic industry” within the meaning of Rules. The Authority has considered the petitioner companies as domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

**D. Initiation of Sunset Review**

11. In view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

**E. Country Involved**

12. The country involved in this investigation is China PR

**F. Period of Investigation**

13. The Authority has considered the period of October, 2016 to September, 2017 as the Period of investigation. The injury investigation period has however, been considered as the period 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the period of investigation.

**G. Procedure**

14. The present sunset review covers all aspects of the final findings published vide Notification No. 15/22/2011-DGAD, dated 20<sup>th</sup> February, 2013 recommending imposition of anti-dumping duty on imports of Flat Base Steel Wheels originating and exported from China PR.
15. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

**H. Submission of information**

16. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,  
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce  
4th Floor, Jeevan Tara Building,  
5 Parliament Street, New Delhi -110001.

[dgad.india@gov.in](mailto:dgad.india@gov.in)

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

**I. Time Limit**

18. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.
19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

**J. Submission of information on confidential basis**

20. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page and accompanied with soft copies.
21. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
22. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons as to why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**K. Inspection of public file**

26. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

**L. Non-cooperation**

27. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Designated Authority